



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2019/भाद्र 1, 1941

No. 260]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2019/BHADRA 1, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2019

[सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के तहत]

(रक्षोपाय जांच)

(मामला संख्या: (एसजी) 03/2019)

विषय: भारत में "फिनोल" के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच की शुरुआत की सूचना।

फा. सं. 22/3/2019-डीजीटीआर.—मैसर्स टीपीएम कंसल्टेंट्स, नई दिल्ली के माध्यम से मैसर्स हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) द्वारा सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (जिसे यहां आगे "उपर्युक्त नियमावली" या "सुरक्षा नियमावली" भी कहा गया है) के नियम 5 के तहत एक आवेदन पत्र दायर किया गया है जिसमें उन्होंने उनके बड़े हुए आयातों के कारण गंभीर क्षति/गंभीर क्षति के खतरे से समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए "फिनोल" (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा संबद्ध सामान भी कहा गया है) के बड़े हुए आयातों का आरोप लगाया है। (इसके पश्चात संबद्ध वस्तुओं का "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पी यू सी" के रूप में भी संदर्भित) के बड़े हुए आयातों जिसके कारण भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों अथवा सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धी उत्पाद से गंभीर क्षति हुई है/गंभीर क्षति का खतरा है, का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया गया है। उन्होंने घरेलू उद्योग की तरह या सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों को गंभीर क्षति से बचाने के लिए और फिनोल के इस तरह के आयात के कारण गंभीर क्षति के खतरे की सुरक्षा के उपाय की मांग की है।

2. विचाराधीन उत्पाद: विचाराधीन उत्पाद "फिनोल" है। यह एक ऑर्गेनिक रसायन है जिसे कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है तथा जिसका प्रयोग फिनोल फॉर्मेलिहाइड रेसिन्स, लेमिनेट्स, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड,

बिसफिनोल-ए, अलकाइल फिनोल, फार्मास्युटिकल, डिफिनाइल ऑक्साइड और निचले स्तर के रसायनों के विनिर्माण में किया जाता है। फिनोल उप शीर्ष 29071110 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है।

3. घरेलू उद्योग: यह आवेदन पत्र फिनोल के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों का भारत में घरेलू समान उत्पाद के कुल उत्पादन में प्रमुख हिस्सा (87 प्रतिशत) है। दोनों उत्पादक सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8बी की उप धारा (6) के खंड (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।
4. जांच की अवधि: वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए मानी गई अवधि 2016-17 से जून, 2019 तक है। आवेदकों ने 2019-20 की पहली तिमाही में आयातों में उछाल का दावा किया है।
5. बड़े हुए आयात: याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान बड़े हैं और उनके सामने बड़े हुए आयातों का खतरा भी आ रहा है। यह नोट किया जाता है कि 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अचानक, तीव्र और काफी वृद्धि हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि मांग आपूर्ति अंतराल है, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध सामानों के अधिकतर आयात भारतीय बाजार में आ रहे हैं जो संबद्ध सामानों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को पूरा करने के लिए अपेक्षित मात्रा से उच्चतर स्तर पर हैं। संबद्ध सामानों के आयातों में वृद्धि की दर पिछली तिमाहियों की तुलना में 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान उनकी मात्रा पर विचार करते हुए काफी मानी जाती है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वैश्विक रूप से फिनोल की अधिक आपूर्ति और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन व्यापार युद्ध से चीन द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अप्रत्याशित परिस्थितियां थीं जिससे भारत में आयातों में वृद्धि हुई।
6. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति का खतरा: आवेदकों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है तथा गंभीर क्षति होने का खतरा भी हो रहा है। एक प्रमुख आवेदक अर्थात् मैसर्स दीपक फिनोलिक्स, जिसने अपना उत्पादन नवंबर, 2018 में शुरू किया, ने 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान उत्पाद के लिए बिक्री और क्षमता उपयोग में काफी गिरावट का दावा किया है और उन्होंने जांच की अवधि के बाद बिक्री और क्षमता उपयोग में और गिरावट होने का दावा किया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध सामानों के आयातों के बाजार हिस्से में 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान वृद्धि हुई है। उन्होंने दावा किया है कि बड़े हुए आयातों के कारण कीमत दबाव के परिणामस्वरूप पहली तिमाही के दौरान उनके लाभ में गिरावट आई है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों की मालसूची में काफी गिरावट है। आवेदकों ने दावा किया है कि चूंकि प्रमुख निर्यातक राष्ट्रों पर चीन जन. गण. द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से इन निर्यातक राष्ट्रों से निर्यात भारत को भेजे जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप में भारत में आयातों में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने यह दावा किया है कि वैश्विक रूप से फिनोल की अधिक आपूर्ति है और उत्पाद की कीमतों में काफी गिरावट आई है। यह दावा किया गया है कि आवेदक कंपनियां उनके ग्राहकों द्वारा उनकी कीमतें कम किए जाने के लिए विवश थीं जिसके परिणामस्वरूप कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास हुआ।
7. आवेदकों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति का खतरा पहुँचाने वाले संबद्ध सामानों के आयातों में काफी वृद्धि को देखते हुए रक्षोपाय शुल्क तत्काल लगाए जाने का अनुरोध किया है।
8. आवेदकों द्वारा दायर आवेदन पत्र की जांच करने के बाद महानिदेशक, प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि विषय वस्तुओं के आयात में वृद्धि अप्रत्याशित विकास जैसे वैश्विक अधिक आपूर्ति और फिनोल उत्पादक देशों के खिलाफ चीन पीआर द्वारा लगाए गए व्यापार के उपायों के परिणामस्वरूप होती है। और इन आयातों की मात्रा और कीमतों ने घरेलू उद्योग के लिए महत्वपूर्ण गंभीर क्षति का कारण या/ और खतरा उत्पन्न हो रहा है।
9. यह निर्धारित करने के बाद कि सुरक्षा जांच की शुरुआत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, महानिदेशक ने सुरक्षा नियमों, 1997 के 5 नियम का पालन करने के लिए एक जांच शुरू की, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अप्रत्याशित क्रम के परिणामस्वरूप, उत्पाद का आयात विचाराधीन आयात में वृद्धि हुई है, और क्या आयात में वृद्धि हुई है या इस तरह के या/और सीधे प्रतिस्पर्धा वाले उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति लगने का खतरा है।

10. सभी हितवद्ध पक्षकार इस सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपने ज्ञात विचार निम्नलिखित को दे सकते हैं:

महानिदेशक

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल, 5, संसद मार्ग,

नई दिल्ली-110001

11. सभी ज्ञात हितवद्ध पक्षकारों को अलग से भी लिखा जा रहा है।
12. जांच से संबंधित कोई भी अन्य पक्षकार जो हितवद्ध पक्षकार माना जाना चाहता हो, अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है जो इस सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर उपर्युक्त पते पर महानिदेशक को पहुँच जाए।
13. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो महानिदेशक रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं। सूचना हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
14. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना – प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्टों/उससे संलग्न अनुलग्नक सहित), प्रश्नावली के उत्तर सहित प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अपेक्षा है कि वे उन्हें दो अलग-अलग सेटों में, यदि उसके किसी भाग में "गोपनीयता" का दावा किया गया है, दायर करें। "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की मार्किंग के बिना किया गया कोई भी अनुरोध महानिदेशक द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और महानिदेशक उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितवद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों रुपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के दो (2) सेटों में हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा। गोपनीय रुपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति में गोपनीय हैं और/अथवा अन्य सूचना होगी जो उस सूचना को देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है, जिस सूचना को प्रकृति में गोपनीय होने का दावा किया जाए अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले से यह अपेक्षा है कि वे दी गई सूचना के साथ उसका सही कारण का विवरण दें कि उस सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता। अगोपनीय रुपांतर में गोपनीय सूचना के साथ, अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा खाली रखा गया (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) और जिस सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है, उस पर आधारित सार का प्रदर्शन होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार में गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार को उपयुक्त रूप से समझने के लिए पर्याप्त ब्यौरे होने चाहिए। तथापि, अपवादस्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि वह सूचना सार में अतिसंवेदनशील नहीं है और कारणों का यह विवरण कि उसका सार करना क्यों संभव नहीं है, महानिदेशक की संतुष्टि के अनुसार दिया जाना चाहिए। महानिदेशक प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि महानिदेशक संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है और यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने का इच्छुक नहीं है अथवा उसे सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकट करने के लिए प्राधिकृत करता है, तो वे उस सूचना को अनदेखा कर सकते हैं। कोई भी अनुरोध, जो उसके सार्थक अगोपनीय रुपांतर के बिना किया गया है अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारणों के विवरण के बिना किया गया है, महानिदेशक द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा। महानिदेशक संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उसे सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।
15. कोई भी हितवद्ध पक्षकार अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।
16. यदि कोई हितवद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में पर्याप्त व्यवधान डालता है तो महानिदेशक उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो उपयुक्त मानी जाती हों।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2019

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

(Safeguard Investigation)**[Case No. (SG) 03/2019]****Subject: Notice of initiation of Safeguard Investigation concerning imports of “Phenol” into India**

F. No. 22/3/2019-DGTR.—An application has been filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter also referred to as the “said Rules” or “safeguard rules”) by M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and M/s Deepak Phenolics Ltd, (herein after also referred to a petitioners or applicants) through M/s TPM Consultants, New Delhi alleging increased imports of “Phenol” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or subject goods) causing serious injury and threat of serious injury to the domestic industry. They have sought safeguard measures to protect the Domestic Industry of like or, directly competitive products from serious injury and threat of serious injury being caused by such increased imports of Phenol.

2. **Product Under Consideration:** The product under consideration is ‘Phenol’. It is an organic chemical, also known as Carboic Acid and used in the manufacture of Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide and downstream chemicals. Phenol is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under the sub-heading 29071110.
3. **Domestic Industry:** The application has been filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and M/s Deepak Phenolics Ltd for imposition of Safeguard Duty on imports of Phenol. The applicants, account for a major share (87%) of the total production of the domestic like product in India. The two producers constitute Domestic industry in terms of Clause (b) of the Sub Section (6) of Section 8B of the Custom Tariff Act, 1975.
4. **Period of Investigation:** The period considered for the purposes of present investigation is from 2016-17 to June 2019. The applicants have claimed surge in imports in Q1 2019-20.
5. **Increased Imports:** The petitioners have claimed that imports of product under consideration have increased during Q1 2019-20, and they are also facing threat of increased imports. It is noted that there is a sudden, sharp and significant increase in imports of PUC during Q1 2019-20. Despite the fact that there is a demand supply gap, the petitioners have claimed that large imports of subject goods are entering into Indian market which are at level higher than required to bridge the gap between demand and supply of subject goods. The rate of increase in imports of subject goods is considered significant considering their quantum during Q1 of 2019-20 as compared to previous quarters. The petitioners have claimed that imposition of anti-dumping duty by China coupled with oversupply of Phenol globally and US China trade war were unforeseen circumstances leading to increase in imports into India.
6. **Serious Injury and threat of serious injury to the domestic industry:** The applicants have claimed that the increased imports of product under consideration have caused and are also threatening to cause serious injury to the domestic industry. One of the major applicants ie M/s Deepak Phenolics which started its production in November, 2018, has claimed significant decline in sales and capacity utilization for the product during Q1 of 2019-20 and they have claimed further decline in sales and capacity utilization post POI. The petitioners have also claimed that market share of domestic industry has declined whereas that of imports of subject goods have increased during Q1 of 2019-20. They have also claimed that their profits have declined during Q1 as a result of price pressures caused by increased imports. The petitioners have further claimed that there is a significant increase in inventories of subject goods produced by domestic industry. The applicants have claimed that since the imposition of anti-dumping duties on Phenol by China PR on major exporting nations, the exports from these exporting nations are getting diverted into India resulting in increase in imports into India. Further the applicants have claimed that there is an oversupply of Phenol globally and the prices of product have declined significantly. It has been claimed that applicant companies were forced by their customers to reduce their prices resulting in price suppression and depression.
7. The applicants have requested for immediate imposition of safeguard duty in view of significant increase in imports of subject goods causing serious injury and threat of serious injury to the domestic industry.

8. After examining the application filed by applicants, the Director General, prima facie, finds that increase in imports of subject goods appear to be result of unforeseen developments such as global oversupply and trade measures imposed by China PR against major Phenol producing countries, and volume and prices of these imports have caused and/or threatening to cause significant injury to domestic industry.

Initiation

9. After determining that there is sufficient evidence to justify initiation of safeguard investigation, the Director General initiates an investigation pursuant to rule 5 of the Safeguard rules, 1997 in order to determine whether as a result of unforeseen developments, the imports of the product under consideration constitute increased imports, and whether the increased imports have caused and/ or are threatening to cause serious injury to the domestic industry of like and/or directly competing products.
10. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

Director General

Directorate General of Trade Remedies (DGTR),

Jeevan Tara Building, 4th Floor

5, Parliament Street,

New Delhi-110001

11. All known interested parties are also being addressed separately.
12. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General on aforementioned address within 30 days from the date of this notice.
13. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Director General may record its findings on the basis of the facts available on record. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.
14. Submission of Information on Confidential Basis – The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the Director General including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Director General and the Director General shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Director General. The Director General may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Director General is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Director General. The Director General on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.
15. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

-
16. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Director General may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General